

ग्रिड संबद्ध सौर पीवी निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिशानिर्देश

पीएफसी ग्रिड संबद्ध सौर पीवी निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को निम्नलिखित के अध्यक्षीन वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकता है:

1. परियोजना मानदंड

- क) सौर पीवी मॉड्यूल लागू बीआईएस मानकों के अनुरूप होंगे।
- ख) राज्य/निजी डिस्कॉम या किसी अन्य स्वीकार्य सरकारी/निजी एजेंसी(ओं) के साथ स्थिर विद्युत खरीद करार (पीपीए) वाली परियोजनाएं।
- ग) कुछ शर्तों के अध्यक्षीन वे परियोजनाएं जो एसपीवी मार्ग या अंतिम उपभोक्ता तुलन-पत्र के माध्यम से कैप्टिव खपत हेतु स्थापित की जा रही हैं।

2. वित्त-पोषण की सीमा

- क) पीएफसी सामान्यतः कुल परियोजना लागत के 50% के वित्तपोषण पर विचार कर सकता है।
- ख) हालांकि, कुछ शर्तों के अध्यक्षीन, पीएफसी एकमात्र ऋणदाता के रूप में परियोजना को वित्तपोषण अर्थात् परियोजना के पूर्ण ऋण घटक (2000 करोड़ रुपए के ऋण तक) प्रदान कर सकता है।

3. ऋण इक्विटी (डी/ई) अनुपात

परियोजना का ऋण इक्विटी अनुपात (डी/ई) 75:25 से अधिक नहीं (अर्थात् इक्विटी परियोजना लागत के 25% से कम नहीं) होना चाहिए। तथापि, कुछ शर्तों के अध्यक्षीन ऋण इक्विटी अनुपात (डी/ई) 75:25 से अधिक और 80:20 तक पर विचार किया जा सकता है (अर्थात् इक्विटी परियोजना लागत के 20% से कम नहीं)।

4. न्यूनतम परियोजना आकार

पीएफसी को ≥ 5 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली परियोजना का वित्तपोषण करना चाहिए।

5. ऋण की पुनर्भुगतान अवधि

ऋण की अधिकतम अवधि (स्थगन अवधि सहित) विद्युत खरीद करार की अवधि या सीईआरसी/एसईआरसी द्वारा यथा परिभाषित परियोजना के आर्थिक जीवन के 80%, जो भी कम हो, तक सीमित होगी। पीएफसी वाणिज्यिक परिचालन तारीख (सीओडी) से 1 वर्ष तक की अवधि के लिए मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु स्थगन की अनुमति प्रदान कर सकता है।

6. प्रतिभूति

- क) परिसंपत्ति पर प्रभार
- ख) व्यक्तिगत/निगमित गारंटी, शेयर प्लेज रखने आदि जैसी कोलेटरल प्रतिभूति परियोजना की एकीकृत रेटिंग के आधार पर पीएफसी की मौजूदा नीति के अनुसार प्राप्त की जाएगी।

7. गारंटी/वारंटी ईपीसी संविदा/पैनल के आपूर्तिकर्ताओं के अंतर्गत, पीएफसी की संतुष्टि के लिए, संपूर्ण ऋण अवधि हेतु उपलब्ध होनी चाहिए।

8. पीएफसी उन सभी मामलों में एलई, एलएफए और एलआईए को नियुक्त करेगा जहां वह परियोजना को एकमात्र ऋणदाता के रूप में वित्तपोषण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अन्य मामलों में पीएफसी को एलई, एलएफए, एलआईए आदि को नियुक्त करने का अधिकार होगा, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए।